[Prof. Madhu Dandavate]

the Railway Board to the lowest echelons of the railways so that a number of young officers and employees who are stagnating will have an opening. That is as far as the restructuring of the Raiway Board is concerned.

In the end, I would like to refer to the Emergency situation. We have been demanding that all the operations and the repressions of Emergency must end. If we have been released and those of us who were in jail have become Ministers today, why should those employees in the railways who suffered during the Emergency only because of certain trade union orientation of their own, only because of their political convictions if they were either thrown in jail under MISA or DIR or sometimes because they were suspected to be the members of the banned organisations, continue to suffer. I do not want that particular position to arise. Therefore, I have made it explicitly clear that those who are subjected to suspension or dismissal or premature retirement as a consequence of Emergency will all be reinstated. Not only that . The disciplinary rule 14(2) was misused to punish certain railway employees. We will review all those cases. As regards those who were suspended for corrupt cases, we are not going to tolerate them. But as regards those who were victimised for their political convictions or trade union activities or political affiliations, because their trade union activities or political affiliations were inconvenient to the then party in power, I say that all these victimised workers will be reinstated. For that, I want to fix the time-limit of six weeks. Within six weeks, we will be able to complete the process. I give this solemn assurance to the House.

Sir, I would conclude my speech by making an important announcement. I thought that I would have been able to make this announcement in my Budget speech. But due to some technical difficulties, I was not able to do it. I will make that announcement today. The Class IV railway employees of the lowest starata have suffered for years and their trade unions have been consistently demandng some promotion for Class IV employees. They have been demanding for selection grades. That was denied to them for all these 30 years. I want to make an announcement on that.

I am aware that the promotion prospects of certain categories of Class IV staff in the Railways are not adequate. Considering this, it has been decided to introduce suitable selection grades to the extent of 20 per cent of the sanctioned posts of the recruitment grades of certain Class IV staff in the non-technical service of the Railways. This will benefit nearly 50,000 Class IV employees in the Indian Railways. It has also been decided that these selection grades will be introduced retrospectively from 1st August, 1976.

This is the announcement that I wanted to make. With that, I conclude.

MR. SPEAKER: We will take up the discussion and voting on the Demands for Grants in respect of the Budget (Railways) for 1977-78 tomorrow.

18.05 hrs.

DISCUSSION *RE*: DETERIORATION IN LAW AND ORDER SITUATION IN SEVERAL STATES

MR. SPEAKER: We shall now take up discussion under Rule 193. Shri B. P. Mandal.

श्री बी० पी० मंडल (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख की बात है कि भारत के अनेक राज्यों में अमन और चैन की स्थिति गड़बड़ा गई है। सब से ज्यादा दुख मुझे अपने राज्य बिहार के कारण हो रहा है जहां पर अभी तक ऐसा सुना नहीं गया था कि चुनाव के दरम्यान खूनखराबी हुई हो। एकाध खून खराबी कहीं शायद हुई हो लेकिन जैसा कि अखबारों से माननीय सदस्यों को मालूम हुआ होगा अब की बार चुनाव के पहले दिन यानी 10 जून 1977 को जिस दिन चुनाव शुरू हुआ भारत के अखबारों में निकला कि वहां 22 आदमी मारे गए आपस की लड़ाई में और दूसरे दिन भी फिर 2 आदमी मारे गए। तीसरे दिन की अभी तक खबर नहीं है। अखबारों में जिन 24 आदमियों के मरने की बात है मेरी जानकारी है कि इस से भी ज्यादा आदमी वहां मारे गए है। गोह एक विधान सभा का क्षेत्र है, गया जिले में पड़ता है। अखबारों में निकला कि दो कडीडेट्स के सपोर्टर्स की आपस की लड़ाई में बन्दूकें चलीं और इतने आदमी मारे गए। लेकिन मेरी खबर है कि कम से कम 12 आदमी वहां मरे है। इसी तरह एकनगढ़, पालीघाट, घोसी, बेगूसराय, छपरा और मुजफ्फरपुर, जिले में हिजरा एक जगह है, इन सारे स्थानों पर आपस के झगड़ों में गोलियां चली और लोग उस से मारे गए। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, इस बार ऐसा हुआ।

हमारे गृह मंत्री भारत में बहुत मशहूर है एक बढ़िया और एबल ऐडमिनिस्ट्रेटर के रूप में और इंटीग्रिटी ऐंड आनेस्टी के लिए उन का नाम मशहूर है। उन के गृह मंत्री रहते हुए ऐसी बात हुई है। मैं समझता हूं कि वे जरा इस बात पर ध्यान देंगे तो जल्दी इस बात को समझ लेंगे कि बिहार में ऐसी बातें बहुत पहले से चल रही है।

1974 में जब विद्यार्थियों का आन्दोलन वहां चला था तो वहां के जिन अफसरों ने निर्दोष लड़कों पर गोलियां चलाने में और वाजिब जुलूस को निकलने देने मे रोकने में कड़ाई दिखलाई थी वही अफसर अब तक वहां है। फिर उन के रहते हुए चुनाव में जो कभी पहले नहीं हुआ वह क्यों हुआ ? पटना के जिला मजिस्ट्रेट श्री एम दुब है। जिन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन के समय अपनी बड़ी करामातें दिखाई थीं। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कांग्रेस रिजीम में बहुत खैरख्वाह समझ जाते थे और आज चार वर्ष से वह पटना में स्थित है। उन के कलेक्टर रहते हुए ही बेलछी गांव में वह घटना घटी जिस पर गृह मंत्री ने यहां बयान दिया। सरे आम दिन में, ब्राड डे लाइट में नौ आदमी वहां आग में जला दिए गए। पटना के बिल्कुल नजदीक यह स्थान है। जिस कलेक्टर ने एमर्जेंसी के टाइम में विद्यार्थियों पर जुल्म करने में और जयप्रकाश बाबू के जुलूस को रोकने में अपनी बहादुरी दिखाई थी वह ला ऐंड आर्डर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सका। मैं सीधा चार्ज लगाता हूं कि इस में अफसरों का हाथ है और उसी कारण बिहार में ऐसी परिस्थिति हुई है जिस के अंदर बेलछी में यह घटना घटी और दूसरी घटनाएं एलेक्शन के टाइम में हुई है। अगर भविष्य में इन बातों को हमारी सरकार रोकना चाहती है तो अभी भी उन राज्यों में प्रेसीडेंट्स रूल है। जो यहां से ऐडवाइजर भेजे गए है मैं समझता हूं कि उनकी भी जवाब देही है, कलेक्टर की जवाबदेही है, एस पी० की, डी आई जी० की और आई जी० की जवाबदेसी है। खास कर थाना अफसर की जवाबदेम

[श्री बी० पी० मडल]

है, वह तो बहुत नजदीक इस जगह से था। गोह में जो आपस में गोली चली है उस का कारण क्या है जब कि सब को मालूम है वहां पर पोलिंग के टाइम पर आर्म्ड गार्ड रहती है, पुलिस रहती है, मजिस्ट्रेट रहता है, पैट्रोलिंग पार्टी घूमती रहती है, तो क्या ये लोग वहां तमाशा देखते रहे ? बिना अफसरों के हाथ के वहां पर इतना बड़ा जुल्म हो नहीं सकता है। हमारे होम मिनिस्टर या हमारी सरकार उन्हीं अफसरों की भेजी हुई रिपोर्ट पर जब यहां जवाब देगी तो हम वाजिब बात पर नहीं पहुंच सकेंगे। मैं गृह मंत्री महोदय से कहूंगा कि बिहार की बहुत बड़ी आशा उनके पीछे लगी हुई है। वे उत्तर प्रदेश और बिहार में कोई फर्क मत समझें। दोनों मिले हुए राज्य है। इसलिए वे बिहार में भी दिलचस्पी लें। मंत्री महोदय सी०बी०आई० या किसी दूसरी ऐसी एजेंसी से इन वारदातों की जांच करवायें और जिस कलेक्टर के जुरिस्डिक्शन में, जिस एस० पी० या दारोगा के जुरिस्डिक्शन में वारदातें हुई है उनके खिलाफ तुरन्त स्ट्रिक्ट ऐक्शन लें। अगर अफसरों को सस्पेंड होने का डर होगा तो फिर ऐसी वारदातें नहीं होंगी।

अध्यक्ष जी, कुछ दिनों के लिए मैं भी बिहार का मुख्य मंत्री था। मुझे याद है उसके पहले बराबर ईद-बकरीद में हिन्दू मुस्लिम दंगे हो जाते थे लेकिन मैं ने अफसरों को डायरेक्शन दिया कि जिस अफसर के जुरिस्डिक्शन में ला ऐंड आर्डर की प्राब्लम होगी, हिन्दू मुस्लिम रायट होंगे उसको तुरन्त सजा दी जाएगी। नतीजा यह हुआ कि सारे बिहार में कहीं भी एक रायट नहीं हुआ। लेकिन ये जो वारदातें आज बिहार में हो रही है, वे आज तक कभी नहीं हुई। ये जो अफसर हैं वे हमारी सरकार के प्रति वफादार नहीं है। अभी जो बिहार में मुख्य मंत्री थे, श्री जगन्नाथ मिश्र, उन्होंने अपने आदमियों को तमाम बिहार में ऊंची-ऊंची जगहों पर रखा है और उन से वे सलाह लेते है। मुझे मालूम हुआ है इस चुनाव में भी अफसरों से काफी मदद की है। बिहार में गत पार्लियामेंट चुनाव में हम ने सब से ज्यादा लीड ली थी, लेकिन आज वहां पर नतीजा भी दूसरा हो रहा है। मैं समझता हुं कि इस के पीछे भी अफसरों की साजिश है। बैलछी की बात अलग है। अमरपुर एक गांव है वहां आज से दस दिन पहले मास-स्केल पर डकैतियां होती रहीं। गत मास 16 तारीख को कुछ आदमी पटना गए थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि जैसे ही गाड़ी महमराम पहुंची, डकैतों ने रिवाल्वर और छुरों से सारे के पार्टमेंट को लूट लिया। आज बिहार में प्रेसिडेन्ट रुल के समय में यह स्थिति चल रही है। इस समय जो आफिसर्ज वहां है, एमर्जेंसी के समय में भी उन का यही रवैया रहा है। ऐसी बात नहीं है कि एमर्जेंसी में वहां की ला-एण्ड आर्डर पोजीशन अच्छी थी। एमर्जेंसी में विद्यार्थियों और जनता के आन्दोलन को दबाने में ये आफिसर्ज सक्रिय थे। एमर्जेंसी के टाइम में पटना के नजदीक दो ही स्टेशन आगे फतुहा स्टेशन पर ब्राड-डे-लाइट में बदमाशों ने एक आदमी का गला काट लिया और दो मील जा कर काली जी के मन्दिर में वह गला चढ़ा दिया। एमर्जेंसी के समय से ही वहां ला एण्ड आर्डर की पोजीशन खराब है। अब इसको और ज्यादा खराब कर दिया गया है। इस पर हमारी सरकार का कड़ाई करनी चाहिये।

दूसरे राज्यों की भी ऐसी ही परिस्थिति है। हमारे साथी श्री कंवर लाल गुप्त दिल्ली की वारदातों के सम्बन्ध में बतलायेंगे,... दिल्ली में भी रोज वारदातें होती है ....

MR. SPEAKER: Mr. Vayalar Ravi and Mr. Kanwarlal Gupta will also be speaking....

श्री बी० पी० मंडल : मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यह जरुरी नहीं है कि ला एण्ड आर्डर मेन्टेन करने के लिए गोली चलाई जाए । मैं गोली चलाने के बिल्कुल खिलाफ हूं । हम ने जलियांवाला बाग में चलाई गई गोली के खिलाफ़ क्रिटिसाइज किया था । कांग्रेस सरकार में जो गोली चली, हम उस के भी खिलाफ़ बोले । हमारे बिहार में, मेरी कांस्टीचुएन्सी में 19 मार्च, 1974 को गोली चली, एक लड़का मारा गया । उस समय बी०एस० एफ० के इंस्पेक्टर जनरल रुस्तम जी थे । उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो यहां बच्चों पर गोली चली, वह यूरोप में इन्टरनल डिस्टरबेंस में कभी नहीं चलाई जाती है । वहां पर रायट-गन इस्तेमाल होती है, रबर-बुलेट्स इस्तेमाल होती है । इसलिए मेरा कहना है कि गोलियां नहीं चलाई जानी चाहिऐ । अगर हम ने जरा भी गोलियां चलाने का इशारा दे दिया तो ये लोग तो खून की नदिय बहा देंगे । हमारी यह सरकार बड़े भारी रेवोल्यूशन के बाद बनी है, इस को बिना गोली चलाए फंशन करना है और अगर कहीं गोली चलानी भी पड़े, तो रबर-बुलेट्स चलाई जाए । मेरा यह विचार है कि कड़ाई करने से, आफिसर्ज को सस्पेण्ड करने से ला-एण्ड-आर्डर स्थिति में सुधार आ जाएगा ।

मुझे केवल इतना ही निवेदन करना था ।

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): Sir, the law and order situation is a matter of anxiety for everybody, irrespective of one's political affiliations. I think it is a matter primarily of the State Governments but it becomes relevant here because the violence took place in the northern parts of the country where many of the States are under President's Rule and thus under the control of the Central Government today. It is very unfortunate that political violence was of such a high order. It may be due to the polls and may be a temporary phenomenon which may not be perpetuated but, nevertheless, certain elements, especially the ruling party, seem to think that they have all the freedom. They definitely have no freedom to take the law into their own hands, to whichever political party they may belong, and deal with the people directly, spreading panic among them and disturbing the peaceful life of the country. In this connection, I would like to refer to certain things which happened in Bihar, about which my friend has just spoken. I am afraid the official calculations of the killings may not be correct. The official death toll in Bihar is 26 but I am afraid it may be round about a hundred. It may be due to political rivalry between two groups but I agree with the hon. Member that the officials failed to prevent this political violence resulting in the death of many people in a State like Bihar.

Another day the Home Minister made a statement in regard to the burning of bodies of Harijans while replying to a Calling Attention motion. In this connection I would invite his attention to the press report which appeared in the 'Sunday Indian Nation'. This report was given by the Police to the Press. I quote:

> "According to police the gang of Singheshwar Mahto was hiding in a house in the village. The gang led by Parameshwar Mahto came to know of it and attacked them by breaking open the house where they were hiding which resulted in the death of eleven persons and caused injuries to three persons.
>
> The source said that the police reached the spot when the accused (Parmeshwar Mahto group) were making an attempt to hide the bodies and succeeded in taking all the bodies into custody".

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDHURI CHARAN SINGH): That report refers to burnt bodies being taken into police custody.

SHRI VAYALAR RAVI: In any case, the report received by me from my friends says that the real culprits, who are very influential people, are still at large. The Home Minister himself has admitted that 50—60 persons were involved in this incident and the people who died belonged to one group and the others could escape without any injuries. How can it be, if it was a clash? The police did not reach in time. This shows negligence on the part of the police and it creates a suspicion in our minds that the whole thing has been cooked up in this way by the police to favour the real culprits and this report has leaked out to the newspapers to create a different story. I hope, the Home Minister will look into this.

I am not going to say anything about West Bengal, where many people died in the poll violence, and this is a State where violence is always there. I am much worried about Kashmir. It is the concern of everybody, whether on this side or that side. We know that Kashmir has a special status in the Indian Union and we want complete peace in the valley because of the sensitive situation there. I do not want to blame Sheikh Abdullah but I would only quote a report from the *Times of India* dated 12th June. It said:

> "The historic town of Awantipore, 30 kms from here, was partially burnt down, about 100 persons were injured and a large number of cars and buses damaged today when violence broke out in the Kashmir valley during electioneering".

And, it is still going on. No doubt, the Home Minister has made a statement regarding recent incidents of violence in Kashmir, but what effective steps is he going to take to prevent violence and ensure a peaceful election in the valley. That is my point. Sheikh Abdullah is ill and I do not want to make any reference to him. The workers of the National Conference Party should be tamed to make the elections peaceful. They should not be allowed to take the law in their hands. They have beaten a lady candidate of Janata Party and she is in the hospital. I hope, necessary steps would be taken immediately to prevent all such happenings.

We all know what has happened in Punjab. In Delhi itself a Congress worker has been killed recently. His name is N. K. Chaddha. He was just walking in the night at 11.00 p.m. and he was killed by Janata Party workers and only one person has been arrested in that connection. I am afraid the police has not taken effective steps to find out the culprits. Delhi is right under your nose and control and this has been done by your own party workers, but you could not take any action against them and have arrested only one man.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): He was a bad character. What you are saying is not correct.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): It is a very convenient version that you can give.

SHRI VAYALAR RAVI: Does it mean that you should kill all the bad characters. I think you should not do that.

In Delhi, during elections there have been many cases of serious violence. Our party people never went to the house of Shri Kanwar Lal Gupta or to the house of Shri V. K. Malhotra. None of the Congressmen burnt their houses, but we know what happened in Punjab. I am sorry to say that a number of people, especially Congressmen, have been killed in Punjab. A person belonging to Janata Party has also been killed in Amritsar. We are

against political killings and I am sorry for what happened there. Here is a report that Shri Raghunandan Lal Bhatia, an ex-Member of Parliament, his father was also a member, is being harassed. His house was raided on the plea that somebody was hiding there. All the ladies of the house had to run away from there. Then, your party workers burnt the house of the DPCC President, Shri Jai Inder Singh and Janata Party workers prevented the Fire Brigade from putting down the fire. The goondas entered the DCC office and burnt it down. The Janata Party has been taking law in their hands. You killed Mr. Chaddha in Delhi. He was a Congress worker. Do you want that the Congress workers should retaliate and go to the houses of Shri Kanwar Lal Gupta and Shri V. K. Malhotra as your people has done in Amritsar. I assure you, we will never do that and we are against this. If you allow me I will quote again what the Police has said about one murder in regard to which Shri Hans Raj Sharma former minister, went on fast.

> "While the Patiala Sessions Court today granted bail to the five Congress workers arrested in connection with the Dera Bassi firing incident last week, the Punjab Police claim to have established the identity of the culprit who still remains at large....."

The Police admit that they could not arrest the real culprit. Yet, you harass the Congress workers and arrest them and put them in jail but you could not arrest the real culprit. You are simply giving protection to people who kill Congressmen. While you are harrassing the Congressmen in Punjab, your workers go and ransack the District Congress Committee office. The hon. Member of Parliament of your party—his name was Dr. Baldev Prasad—I wish that some sense would come to him. This is the way the whole thing is happening in the country. This kind of political violence has to be put an end to, violence by any party whether your party or our party.

Lastly, in Delhi I hope hon. Members will be very much concerned about the jail break in the daylight by the followers of the late Sunder Daku. The hon. Minister has been kind enough to start an inquiry into the death of Sunder Daku and the reported molesting of his sister. I do not know whether he has seen a report in the Press that Mr. Sunder had no sister at all. Yet he is making an inquiry into it. Five people who were in the jail could escape in broad daylight in Delhi. Everyday reports come in the press that people are murdered in Delhi. We are seeing reports of DSPs and DIGs coming and going but you have completely failed to maintain law and order in Delhi. We all live in Delhi with our families. Robberies taking place in daylight. Life in Delhi has become insecure.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDHURI CHARAN SINGH): Does the hon. Member know that 12 prisoners escaped from Tihar Jail? They were prisoners under your rule.

SHRI VAYALAR RAVI: That will not justify this.

The escape of prisoners shows the failure of the administration whether it happened under the Congress rule or the Janata Party rule. But here daylight break from jail takes place and the prisoners escape from Delhi and you could not arrest them so far. Later the report of certain murder comes, and I don't want to name any people.

Lastly, there is this para-military force functioning in the country. They are taking law and order in their hands. You cannot maintain law and order with this para-military force. It is RSS. Theirs is a big force and they have been given armed weapons training. I do suspect they are given full freedom and respectability. That is

[Shri Vayalar Ravi]

the reason for political violence which is day by day increasing in the country. If you think you can control the freedom of the political parties and intimidate workers of other political parties using RSS, may I remind you that you are sadly mistaken. Do you believe that you have the freedom to kill people? You have to protect the right of the people to function and work in this country and carry on their legitimate politieal activities.

With these words I will appeal to the Minister through you that paramilitary forces like the RSS are a danger to democracy which will crush the freedom not of the Congress Party alone but even your own freedom.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : श्री रवि के भाषण को सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छा होता अगर उन्होंने पोलिटिकल मोटिव से भाषण न किया होता और तथ्यों को सामने रख कर सुझाव दिए होते। उनको शायद मालूम ही नहीं है। कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है या नहीं यह अलग बात है। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि एमरजेंसी के दिनों में भी बहुत गुंडागर्दी होती थी। आज तो गुंडे गड़बड़ कर सकते हैं और पहले भी करते थे लेकिन एमरजेंसी में स्टेट ने स्टेट के चीफ मिनिस्टर्ज ने और बड़े बड़े मंत्रियों ने जो गुंडागर्दी की उसकी मिसाल भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगी। हरियाणा में अभी एक कमीशन बिठाया गया है। मैं श्री रवि से पूछना चाहता हूं। क्या यह सही नहीं है कि वहां के मुख्य मंत्री के आदेश से पुलिस के अफसरों ने बहन और भाई को नंगा करके, दबाव में लाकर एक खाट पर सोने के लिए मजबूर किया था? क्या यह गुंडागर्दी की हद नहीं थी? यह सही है कि चाहे जनता सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो नागरिकों को सुरक्षित जीवन बिताने का अवसर मिलना चाहिए, उस में किसी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं होनी चाहिए, उनकी सम्पत्ति सुरक्षित रहनी चाहिए। कुछ लोगों ने जो गुंडागर्दी की है उसका मुझे अफसोस है और उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मुझे मालूम नहीं है कि जो तथ्य माननीय सदस्य प्रस्तुत कर रहे थे वे सही थे या नहीं।

आज तीन आदमी चले गए हैं जेल से दिल्ली में। लेकिन क्या माननीय सदस्य को मालूम है कि चालीस फुट की टनल बना कर और तीन महीने तक उसको खोदते रह कर इनके राज्य में तेरह आदमी जेल से भाग गए थे जिस की खबर आज तक अखबारों में नहीं आई है....

SHRI VAYALAR RAVI: That is why you are justifying it?

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं चाहता हूं कि हर किसी को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। हर एक के मन में यह भावना होनी चाहिए कि मैं सेफ हूं, मेरी प्रापर्टी सेफ है। आप स्टेटिसटिक्स को छोड़ दें। वे दोनों तरह के हैं। स्टेटिसटिक्स ये भी कहते हैं कि दिल्ली में कुछ कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ी है। इसको ठीक किया जाना चाहिए। लेकिन इसके भी कुछ कारण है। आजकल अखबारों पर सेंसर नहीं है जो पहले था। पहले पूरी रिपोर्टें नहीं आती थीं आज पूरी आती हैं। पहले उनको दर्ज भी नहीं किया जाता था, आज उनको किया जाता है। एक कारण है यह भी कि पहले पुलिस पुलिसिंग नहीं करती थी। पहले पुलिस किसी को भी पकड़ कर मीसा में डाल देती थी। तब रूल आफ जंगल था। आज वह बात नहीं है। दोनों का इस वास्ते आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मीसा में हमको बन्द किया गया। वहां हमारे साथ कम से कम एक हजार लोग ऐसे थे जो बैड कारेक्टर्ज थे। आज साधारण जो कानून है उसके जरिए से ला एंड आर्डर की स्थिति को ठीक किया

जा रहा है। इस वास्ते दोनों का कोई मुकाबला नहीं है।

मैं मानता हूं कि जनता पार्टी से लोग ज्यादा अपेक्षा करते हैं। कांग्रेस से वे ज्यादा अपेक्षा नहीं करते थे। इस वास्ते हमारी सरकार को ज्यादा सतर्क होना चाहिए और इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जनता की जो अपेक्षाएं हैं, डैमोक्रेटिक ट्रेडीशंन को रखते हुए, उनको मेंटेन करते हुए हमें पूरी करनी है।

एक दुख की बात है। पुलिस एक्ट 1861 का बना हुआ है। एक सेंचरी पहले बना था। उस में कोई बदल आज तक नहीं किया गया है। अंग्रेजों ने सौ साल पहले जो बनाया था वही आज भी चला आ रहा है। स्टेट लेवेल्ज पर आपने पुलिस कमिशन्श बिठाए हैं। लेकिन आल इंडिया लेवल पर कोई नहीं बिठाया। चेंज्ड सरकमस्टांसिस में, इकोनोमिक, सोशल, पोलिटिकल आदि क्षेत्रों में जो चेंजिज आई है उनको सामने रखते हुए हमें चाहिए कि हम आल इंडिया पुलिस कमिशन बिठाएं जो साइंटिफिक ढंग से जो काइम्ज किए जा रहे हैं उनको स्टडी करे, यह देखे कि पुलिस के लोगों को क्या क्या एमेनेटीज दी जानी चाहिएं, किस प्रकार की उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, पुलिस फोर्स को मार्डनाइज कैसे किया जाए और वह अपने सुझाव दे।

अभी करीब 11000 पुलिस स्टेशन हैं। एक पुलिस स्टेशन का एरिया करीब तीन सौ स्क्वेयर मील का होता है। जो डिवेलेप्ड कंट्रीज हैं उनके मुकाबले में हमारे यहां काइम्ज का जो रेट है वह बहुत कम है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम कुछ न करें। हम को चाहिए कि इस रेट को हम जितना कम कर सकते हों करें। हमें लोगों को पूरी सुरक्षा प्रदान करनी है। बजाए इसके की कार्रवाई हो जाए, काइम कमिट कर दिया जाए और उसके बाद पुलिस हरकत में आए, पुलिस को पहले से ही उसको रोकने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए।

माननीय सदस्य ने पैरा मिलीटरी की बात कही है। मैं पालिटिक्स नहीं लाना चाहता हूं। लेकिन मैं नाम बता सकता हूं रवि जी को दस नहीं पचास नाम बता सकता हूं जो हिस्ट्री शीटर्ज थे उन्होंने यूथ कांग्रेस में जा कर लाखों रुपया कमाया। आज वह फिर हिस्ट्री शीटर्स गुंडागर्दी कर रहे हैं

These people are responsible for deterioration of law and order. I demand of the Home Minister that he should take stern action against them.

जिस केस के बारे में माननीय रवि ने कहा है उस में किस प्रकार के आदमी हैं मैं जानता हूं।

Let there be an enquiry. I will demand that there should be an enquiry.

दो गुंडों के बीच की लड़ाई थी और उस में वह मारे गये। अगर आप इनक्वायरी कराना चाहते हैं तो करा लीजिये, मुझे खुशी होगी।

केरल में दो, तीन बच्चों को पकड़ कर पुलिस ने उन को जेल में मारा। उस सिलसिले में दो डी० आई० जी० सस्पेंडड हैं, चीफ़ मिनिस्टर के ऊपर भी कार्यवाही हो रही है। सुन्दर डाकू को मार दिया गया, उस बारे में यहां पर आप ने एक इनक्वायरी बैठायी। उसी तरह से सुरजीतपाल को मार दिया गया लेकिन उस केस में आप ने एक इंस्पेक्टर और एक ए० एस० आई० को सस्पेंड किया है। जब तक आप बड़े बड़े [illegible] पर हाथ नहीं डालेंगे,

[श्री कंवर लाल गुप्त]

के खिलाफ़ कार्यवाही नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं बनेगा । जीवन सब का सुरक्षित है चाहे वह कोई इन्सान हो, फिर जब इन दोनों केसेज में यह साबित हो गया है कि कि दोनों को मारा गया है और यह काम आई० जी, डी० आई० जी०, एस० पी० की सर्ची के बगैर नहीं हो सकता इसलिए उन के खिलाफ़ भी कार्यवाही होनी चाहिये। छोटी मछलियों को पकड़ने से काम नहीं चलेगा, बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी आप को कार्यवाही करनी चाहिये ।

दिल्ली पुलिस के रेक्रूटमेंट में बड़ी धांधली चलती है, काफ़ी पैसा खाया जाता है । रेक्रूटमेंट के लिये सरकार को अलग से एक मशीनरी बनानी चाहिये और आज जो नौकरी देने के लिये पैसा खाया जाता है इस को बन्द करना चाहिये । दिल्ली में एक कमिश्नर आफ़ पुलिस होना चाहिये । ऐसा न होने से काम डिवाइडेड रहता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अलग काम करता है, और पुलिस वाले अधिकारी अलग काम करते हैं । जिस की वजह से कोई कोआर्डिनेशन नहीं रहता है । और जब तक कोआर्डिनेशन नहीं होगा तब तक कोई कार्यवाही नहीं होगी । पहली सरकार ने भी मान लिया था कि दिल्ली में एक कमिश्नर आफ़ पुलिस होगा, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । गृह मंत्री जी इस बारे में उचित कदम उठायें, यह मेरी मांग है ।

दिल्ली पुलिस के बारे में 10, 12 साल पहले खोसला कमीशन बनाया गया था जिसने कुछ सिफारिशें की थीं । पिछली सरकार ने उस कमीशन की बहुत कम सिफ़ारिशों को माना । खोसला कमीशन ने पुलिस कर्मचारियों के हाउसिंग और बच्चों के स्कूलिंग के बारे में जो सिफारिशें की थीं उन के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की । मेरी मांग है कि उस कमीशन की सिफारिशों पर अमल होना चाहिये । उन के हाउसिंग, बच्चों की स्कूलिंग के बारे में, मौडर्नाइज्ड तरीकों के बारे में कार्यवाही होनी चाहिये । उन की मोबिलिटी होनी चाहिये, ट्रेनिंग ठीक होनी चाहिये । और जब तक इन बातों को कार्यान्वित नहीं किया जायेगा तब तक पुलिस अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर सकेगी । आप देखिये कि दिल्ली में जो एस० पी० हैं वह आफिस में बैठ कर अधिक समय टेबिल वर्क करते हैं और फील्ड में कम जाते हैं । जब तक सीनियर अधिकारी फ़ील्ड में नहीं जायेंगे तब तक पुलिस प्रशासन ठीक से नहीं चलेगा । आप उच्च पुलिस अधिकारियों को आदेश दीजिये कि वह फ़ील्ड में जा कर काम करें ।

दिल्ली में प्रोफशनल बेल देने वाले बहुत हैं । मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर विचार करे कि एम० आई० एस० ए० बैंड करेक्टर्स पर लगाना चाहिये कि नहीं ? इस केस को या इस पौइंट को दोनों तरह से प्लीड किया जा सकता है, लेकिन सरकार जरूर इस पर विचार करे कि एम० आई० एस० ए० बैंड करेक्टर्स पर लगाना चाहिये कि नहीं । और अगर नहीं लगाते हैं तो कम से कम जो प्रोफ़ेशनल बेल देने वाले हैं उन पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये जिस से वह बेल एक्सेप्ट न कर सकें । इस तरह की कोई भी व्यवस्था होनी चाहिये जिस से वह लोग ठीक से रह सकें ।

यहां पर गुंडों को एक्सटर्न करने की बात कही गई है और उस पर बाम्बे एक्ट लागू है । बाम्बे एक्ट के मुताबिक गुण्डों को एक्सटर्न करने में बहुत देर लगती है, इस के लिए राजस्थान एक्ट ज्यादा ठीक होगा ।

अगर राजस्थान का ऐक्ट यहां लगायेंगे तो वह ठीक होगा

जहां तक हम यह कहते हैं कि पुलिस गलत करती है, यह सब कुछ करती है, हम यहां पुलिस का मोरेल गिराना नहीं चाहते हैं, हमें उस के मोरेल को ठीक करना है और उस के लिए पब्लिक से को-आपरेशन लेने की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से हो । पब्लिक की को-आपरेशन से पुलिस वाले कुछ काम कर सकेंगे तो ला एंड आर्डर की हालत ठीक हो सकती है ।

मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टीगेशन, ला एंड आर्डर और सर्वेलैंस इन तीनों के डिपार्टमेंट अलग अलग हों । अब क्या होता है कि जब कभी कहीं झगड़ा होता है तो सब को एक साथ झोंक दिया जाता है और इससे इन्वेस्टीगेशन का काम पीछे पड़ जाता है । और काम रुक जाता है और इस तरह से कन्फ्लिक्ट्स बच जाते हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि पुलिस एक्ट जो 1861 का है, उस में आल इंडिया लैवल पर संशोधन करें, आल इंडिया एक कमीशन बिठायें जो कि 100 साल पहले बने हुए एक्ट को आज की हालात के मुताबिक बदल सके और सब सवालों को स्टडी कर के जो आज की हालत की जरूरतें हैं, उसके मुताबिक ठीक कर सकें । मैं यह भी मांग करूंगा कि पुलिस को जो सुविधाएं देनी जरूरी हैं वह भी उन को पूरी तरह से मिलनी चाहियें जो कि खोसला कमीशन ने रिकमैंड की हैं । इसी तरह से अगर मिलकर काम करेंगे तो यहां की हालत ठीक होगी ।

MR. SPEAKER: Now, no new names can be added to the list that I have already got here. There are four more names. The Minister also must be given ten minutes at least. So, if you make it short by not repeating what the other hon. Members have said, I would be able to give a chance to one more Member. I shall call the hon. Minister at five minutes to Seven. He must also have five minutes to reply to the points raised by the hon. Members.

My difficulty comes only when you give more names from your side.

Shri Lakkappa.

SHDI K. LAKKAPPA (Tumkur): Mr. Speaker, Sir, it is an important and useful discussion really that has been raised by the Members from the other side. My friend, Shri Ravi has made certain points. The hon. Home Minister is an upright Minister of the Janata Party Government. Of course, I have no personal acquaintance with him. That is because I am basically a Congressman. He has got a good reputation. I am very happy about that.

MR. SPEAKER: Why can't you put that in writing?

SHRI K. LAKKAPPA: I am not going to give a certificate. He has a varied experience in administration. I would however like to bring to his notice the enormous increase in political violence in this country whether it is in the States where we are running the Government or at the Centre where you are running the government. Let me quote what happened from April onwards.

In Gujarat, particularly, the present Government is run by the Janata Party. There are instances about which a harijan minister has made a statement regarding the harassment of harijans being on the increase. He has narrated 45 specific cases of harassment. As a consequence of such a harassment, 200 harijans of Valagamada village in Gujarat had left that village completely. It may be due to political rivalry or group hatred but the entire situation

[Shri K. Lakkappa]

in this country, after the Lok Sabha elections, has worsened. I have seen Janata party workers tearing off Congress party flags. It may be in Karnataka, Andhra or Bihar. The previous government had done something good to protecting the interests of the weaker sections. As such, this government has got the onerous responsibility to see to it that protection is provided to all the weaker sections of the country. It may be the Congress workers beating the Janata workers but I am saying that after the Lok Sabha elections in every part of the country an impression has been created that police people are not acting. I find the police officers are terribly afraid everywhere. There is an infiltration of the para-military organisation, namely, R.S.S. That is why I am bringing this to your notice. They may infiltrate in the recruitment system of the police. I hope the hon'ble Home Minister is already aware of all these things. He knows how infiltration has taken place in the Janata party of para-military elements. This is very dangerous for the society. Ultimately this government will be responsible for any violence or violent activities that may take place in this country. It is in this context that we are suggesting amendment in the recruitment system. There is something wrong with the recruitment system as vested interests and reactionaries have infiltrated already in various organisations. The situation is worse so in the present government as these elements are taking advantage of the present government. A para-military organisation is working as a parallel. It is perpetuating and giving training. Everywhere they are raising their head and creating an atmosphere of animosity. Therefore, the present government has got a responsibility to make a special assessment of the situation.

Will the Home Minister kindly appoint an impartial parliamentary committee belonging to all parties to find out the facts and see as to how many Harijans have been harassed in this country? There is flagrant violation of the Central Act meant to protect the weaker sections. There is large-scale boycotting of the Harijans. Harijans are not allowed to draw water or take rations. In view of these circumstances, I am requesting the Home Minister to create a special cell in the Home Ministry to protect the interests of the weaker sections in the country.

SHRI S. KUNDU (Balasore): Sir, after hearing my friends from the Congress benches, I thought as if the whole world has gone wrong within two-and-half months. One of the Members, Mr. Ravi has started saying 'political killings' and he may think we are responsible for that. He has said it in his own inimitable style and he wanted to make us responsible for that. Another ebullient and vociferous Member, Mr. Lakkappa, went to the extent of saying that there has been an enormous increase in political violence. I am sorry to say that these two gentlemen will never read the writings on the wall and never see the light of the dawn of freedom which has been restored by the Janata Government.... (*Interruptions*)

Freedom to live freedom to think...

MR. SPEAKER: Elections are over now.

SHRI S. KUNDU: Freedom not to be tortured as Rajan was tortured in Kerala, freedom not to be tortured as Mr. Fernandez was tortured but freedom to live among people as you are now living. Perhaps you have never tasted it and now you taste it. You remained in one party rule all along... (*Interruptions*)

Sir, I would like to say here that with the strongest hand, wherever there is any sort of goondaism, robbery, dacoity, killing, etc. the Hon'ble Home Minister must ruthlessly suppress them. Whether it is Indira brigade or Sanjay brigade or any paramilitary force, if

it is there, if there is any link with this sort of activity, it must be curbed and suppressed. I am happy that you are taking action on this. Therefore, when we speak of political violence when we speak of political killings, I would like the hon. Members to view it from a different angle. During the last 30 years of Congress regime, we spent crores of rupees on police. It was Rs. 30.0 crores and now we are spending Rs. 300 crores. But political violence and political killings have been increasing day by day. We have not been able to solve it. We do not know whether this can be stopped with the help of bullet of 'danda' or some sort of sociological problem is involved. We do not know whether these people are denied of justice at all levels, even by the politicians, even by the courts, even by the Police or even by the Tahsildars. Sometimes out of frustration wherever youth have been unemployed for years and years, they become angry. We must look into this aspect of the problem.

As Mr. Gupta has suggested, a time has come when we must also see and reorient the police force, make radical changes in the outlook of the police. I find the whole impression about Delhi goes down when I get into a taxi or a scooter in Delhi. I think it is so bad. Why these people go on deceiving us. Why the administration has not been able to motivate them? I have no complaint against them because I know they are completely uprooted, their lands have been taken away and their houses have been uprooted. There is no house for them to live in. But what is the police doing? The police have not been able to motivate the people who are strangers and outsiders. Therefore, this problem should not be judged only with the strength of the police force of the Janata Government. This has to be judged from the sociological point of view. We are very much concerned about the situation in Kashmir and in Nagaland. In Nagaland there was recurrence of violence. I do not know. Many persons say many things. They say that it has been done deliberately by a group of people to give bad name to the Janata government because it did not agree to elections in Nagaland. I do not know; the hon. Home Minister may say about these things. Kashmir is a sensitive area and we must be cautious in sensitive areas and see that such things do not recur. The question of Bihar has been mentioned.

MR. SPEAKER: Please do not repeat: it has been referred to already.

SHRI S. KUNDU: I do not want to repeat. These incidents cause us concern and I hope the Home Minister will reply to these points.

SHRI CHITTA BASU (Barasat): I shall restrict myself to events in West Bengal. You will agree with me that a singular phenomenon in West Bengal last year was the political killings on a large scale and the gangsterism of political elements there. After the assembly elections in 1972, the Congress party came to power—I think Mr. Ravi would know—the then Chief Minister wanted to fortify his position, after he came to the assembly by large scale rigging in 1972 general elections to West Bengal Assembly. He did so by taking resort to gangsterism by encouraging hoodlums, by offering arms to the hoodlums in connivance with the police administration. I know that the plan was masterminded by the government; it was the then Chief Minister who did it. I do not want to mention his name. He masterminded the entire conspiracy and organised these things, sometimes on salaries of upto Rs. 100 per person per month. They were also paid for each killing. There was killing at roads, killing in homes and even in jails. The offices of the left opposition were forcibly occupied by their gangsters in col-

[Shri Chitta Basu]

laboration with the police administration, aided and abetted by the then Chief Minister. Trade unions were emasculated; workers were driven out from work.

AN HON. MEMBER: How is it relevant?

MR. SPEAKER: It is old story; we are now talking of law and order today.

SHRI CHITTA BASU: In that background they also wanted to have elections. Barrakpore provides an example of how large scale rigging took place. Even during the recent assembly elections, what happened? One candidate, Radhika Banerjee was aimed at and fired; unfortunately somebody sitting beside was killed; he escaped.

The same type of thing happened in Belighata. There was large scale killing in Baranagar and Barasat. Seven young men were killed; they were shot dead and their bodies were placed on the open road. All those things were pre-planned and they were intended to terrorise people and stifle the voice of dissent. This has been the back-ground. My humble submission to the hon. Home Minister is this. All newspapers in West Bengal have published so many stories of this nature, horribe stories.

19.00 hrs.

Thousands of people have been killed in open day light even in the jails. Such horrible stories are there. May I know whether the Government of India would take proper note of it? All these are happening because of the political motivation of a particular party. It is political violence which should be dealt with from the political angle and on political platform. My humble suggestion is that a committee of Members of Parliament be formed to go into this question of political violence which is taking place now all over the country in depth. I do not like to mention any particular State. Unless we eradicate this problem of political violence, the law and order situation cannot satisfactorily improve. This is not a question which can be wished away. It is not a question of this party or that party. It is a question which involves all of us, whether we belong to this side of the House or that side. Political violence has to be eliminated. Political gangsterism has to be condemned. For that purpose, a proper atmosphere has to be created so that all political parties have the freedom to work among the masses, so that there may be a good political climate and democracy may function properly.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निज़ामाबाद): अध्यक्ष महोदय, हमारे चौधरी चरण सिंह जी आज उसी स्थान पर बैठे हैं जहां सरदार पटेल और पं० गोविन्द बल्लभ पंत जी बैठते थे। हमारे उन महान व्यक्तियों ने जो काम किये थे, हमारे चौधरी साहब से भी हम उसी तरह के कामों की उम्मीद रखते हैं। आज देश में जो कानून और व्यवस्था इतनी खराब हो गई है, इस की क्या वजह है? मैं चौधरी साहब से बिनती करता हूं, आप ज्यों ही होम मिनिस्टर बने, आप ने सब को कहा कि एकदम फीअरलेस हो जाओ, आप के मन में कोई भय न हो। इसका नतीजा यह हुआ कि जितने गुण्डे थे, दादागीरी करने वाले लोग थे, हॉडंर्ज थे, मटका खेलने वाले थे, जुआ खेलने वाले थे, स्मगलिंग करने वाले थे, उन के दिल से भय बिलकुल निकल गया और आज वे खुले-आम क्राइम्ज कर रहे हैं।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि हर छोटी-बड़ी बात के लिए आप कमीशन मुकर्रिर करते जा रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि हर पुलिस वाले की हिम्मत टूट गई है अगर कहीं गड़बड़ होती है तो पुलिस वाला उधर नहीं जाता है, दूसरी तरफ़

जाता है, क्योंकि उधर जाये और गोली या लाठी चलाने की जरूरत पड़े तो उसे डर है कि कमीशन बैठ जायगा और उस की नौकरी चली जायेगी । आप ने जेलों में जितने क्रिमिनल्ज थे, नक्सलाइट्स थे, सब को एक दम छुटकारा देने का हुक्म दे दिया है . . .

श्री गौरी शंकर राय (गाजीपुर) : क्या नक्सलाइट्स क्रिमिनल्ज होते हैं ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : जी नहीं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, उन को जरा छोड़ कर देखिये, सब मालूम हो जायेगा ।

श्री गौरी शंकर राय : मेहरबानी कर के नक्सलाइट्स को क्रिमिनल्ज न कहिये ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : बहुत अच्छी बात है, सब को छोड़ दीजिये । आप ने जितने क्रिमिनल्ज हैं उन सब को छोड़ने का हुक्म दे दिया है, इसका नतीजा क्या होगा ? देश की आर्थिक स्थिति खराब होगी, फैक्ट्रीज बन्द हो जायेंगी । हर रोज सुबह अखबार उठा कर देखिये—कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब कि दो-चार हत्यायें न हुई हों । हत्याओं को आप चाहे आत्म-हत्याओं में बदल दीजिये, कुछ भी कीजिये, लेकिन यह बात सच है कि देश में हत्यायें बहुत हो रही हैं । इस समय गवर्नमेंट को चलाने की जिम्मेदारी आप के हाथ में है । अपोजीशन की तरफ़ से पूरी-पूरी मदद देने की बात, कंस्ट्रक्टिव कोआपरेशन की बात, हमारे लीडर कह चुके हैं । हम सब आप के साथ हैं, मेहरबानी कर के देश में शान्ति कायम कीजिये, ताकि देश आगे बढ़ सके । हमारे जो भूतपूर्व होम मिनिस्टर्ज हो चुके हैं उन के नक्शे-कदम पर चल कर इस देश का नाम रौशन कीजिये ।

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह): अध्यक्ष महोदय, माननीय मित्रों ने जो कुछ कहा है, उस से मेरे ज्ञान में कुछ इजाफा हुआ है । मैं उन को इस के लिए धन्यबाद देता हूं अगरचे रचनात्मक सुझाव बहुत ही कम दिये गये हैं । पहले तो यह एज्यूम कर लिया गया है कि दो महीनों के अन्दर क्राइम्स बढ़ गये हैं । अब उस के लिए क्या आधार है मेरे दोस्तों के पास ? कोई आधार नहीं है । कहीं कोई एकाध रिपोर्ट निकल गई है कि 200 हरिजनों ने गांव को छोड़ दिया और बेलची गांव की बाबत टाइम्स आफ़ इण्डिया में रिपोर्ट आई और यह एज्यूम कर लिया गया कि क्राइम्स बढ़ गये हैं । बस यह एक साइकोलोजीकल चीज हैं । आखिर मेरे जो दोस्त उधर बैठे हैं उन को कुछ तो कहना चाहिए था उन लोगों के खिलाफ़ जो उधर बैठे हैं या फिर कहीं कोई चोरी हो गई या डाका पड़ गया तो रोज अख़बारों में निकलता है क्योंकि यह एक बहुत अच्छा मजमून है लेकिन कोई इन को साबित नहीं करता है । यह भी कहा जाता है कि गुण्डाज आर नाऊ फ्री । ठीक है । गुण्डों का शायद आप भी फ्री कर देते लेकिन इतिफ़ाक ऐसा है कि पहले जो प्रधान मंत्री थीं, जिस वक्त उन्होंने मीसा हटाया—सैक्शन 16 ए वगैरह वगैरह—और दूसरी चीजें हटाई, तो ज्यादातर गुण्डे उसी वक्त छूट गये थे । गुण्डों की आजादी शायद कुछ इस के लिए जिम्मेदार है जो आज कल हो रहा है लेकिन यह दोष हमारा नहीं है । गुण्डों को तो पहले ही उन्होंने छोड़ दिया था । मैं उन को दोषी करार नहीं देता लेकिन मैं फैक्ट के तौर पर बता रहा हूं कि हम ने थोड़ा ही उन को छोड़ा है ।

गुण्डों की प्राब्लम एक बड़ी भारी प्राब्लम है । पहले भी थी और आज भी है । गुण्डा प्राब्लम यह है कि उन के

[चौधरी रन सिंह] :

खिलाफ़ पुलिस को कोई गवाही नहीं मिलती है, कोई विटनेस नहीं मिलता है । सब से बड़ी प्राबलम यही है। खैर, हम ने यू० पी० में एक एन्टी गुण्डा कन्ट्रोल एक्ट बनाया था और उस से हम को काफ़ी सहूलियत हुई । राजस्थान ने उस के बाद उस में कुछ और इम्प्रूवमेंट किया ।

अब दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, और यह हो गया है और वह हो गया है । ठीक है, हुआ होगा क्योंकि श्री कंवरलाल गुप्त जो कहते हैं उस की मैं तरदीद नही करता । वे शहर के अन्दर रहते हैं और रोजाना लोगों से मिलते-जुलते हैं । उन का इम्प्रेशन सही होगा लेकिन आम तौर पर जो यह इम्प्रेशन बना हुआ है । उस से मैं सहमत नही हू । गुण्डों को कन्ट्रोल करने की जो बात है, वह बड़ी मुश्किल बात है । मैं दिल्ली के अफ़सरों के साथ दो मीटिंगें कर चुका हूं अगरचे मैं यह तसलीम करता हूं कि जितना मुझे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए था, उतना मैं नही दे पाया हूं और इस का कारण यह है कि उस से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मेरा सारा समय ले लेती हैं । जैसे ही मैं उन से निपटा, मैं वायदा करता हूं कि और ज्यादा समय इस में लगाऊंगा ।

यह जो गुण्डा कन्ट्रोल एक्ट है, बम्बई एक्ट यहां पर नाफ़िज है और बम्बई में गुण्डों को कन्ट्रोल करने की बात अच्छी चल रही है । ऐसा हो सकता है कि कहीं प्रोसीजर में ग़लती थी । इसलिए मैं ने दो अफ़सर बम्बई भेजे । वे वहा पर गये और कुछ दिन अध्ययन करने के बाद आज ही उन्होंने मुझे रिपोर्ट भेजी है । जिस वक्त मैं हाउस में आ रहा था, वह रिपोर्ट मुझे मिली और मैं केवल उस का कवरिंग लेटर ही पढ़ पाया हूं । पूरी रिपोर्ट मैं नहीं पढ़ पाया । लेकिन मैं ने वह रिपोर्ट होम सेक्रेटरी को दे दी है और उनसे कहा है कि उस को पढ़ कर मुझ से डिस्कस करें। गुण्डा प्राब्लम ही ला एण्ड आर्डर की मैन प्राब्लम है क्योंकि उस में पुलिस को गवाही नहीं मिलती है ।

इस के बाद बेल की बात आती है । बेल मे बड़े बड़े जो कातिल हैं या डाकू हैं, जिन के खिलाफ़ एलिगेशन्स हैं और एविडेंस में भी जो चीज डाके में लूटी जाती है वह उस के मकान पर मिल जाती है, लेकिन फिर भी उस को बेल पर अदालत छोड़ देती है । उस ने फिर जुर्म किया और फिर उसी अदालत में वह बेल के लिये जाता है और उस को फिर छोड़ दिया जाता है । इस तरह से आसानी से उन लोगों को बेल पर छोड़ दिया जाता है और पुलिस को गुण्डों के खिलाफ कोई गवाह भी नहीं मिलता है । इसलिये यह एक बहुत बड़ी प्राब्लम है, जिस का हल निकालने की जरूरत है । अब प्रश्न यह है कि बेल के अधिकार इनको दिये जायें या न दिये जायें । अगर दिये जायें तो बहुत से लोग इसको लिबरल्ली इस्तेमाल करते है । गांव वाले जानते है कि इस आदमी ने कत्ल किया है लेकिन वह जमानत पर आ जाता है । उसके खिलाफ गवाह नहीं मिलता । खैर ये सब लम्बी चौड़ी बातें है, मैं इनको अभी छोड़ देता हूं ।

कहा जाता है कि कमीशन बिठाने से पुलिस में डिमारेलाइजेशन हो गया है । कमीशन पुलिस वालों के खिलाफ नहीं बिठाये गये हैं । कमीशन उन्ही के खिलाफ बिठाये गये हैं जिन्होंने ज्यादतियां की हैं । हो सकता है कि कुछ पुलिस वालों ने भी ज्यादतियां की

हों और वे ज्यादतियां उन्होंने पोलिटिशियंस के आर्डर पर की हों, कुछ बड़े अफसरों के कहने पर की हों। लेकिन ये कमीशन जो मुकर्रर हुए हैं वे पोलिटिकल लेबल पर जो ज्यादतियां हुई हैं, हायर लेबल के कहने पर जो ज्यादतियां हुई हैं उनकी जांच पड़ताल करने के लिये हुए हैं। अगर इसमें कुछ पुलिस वाले जिन्होंने ला का गलत इस्तमाल किया है वे डिमारेलाइज होते हैं तो क्या कमीशन मुकर्रर न किये जाये ?

दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाती है कि इसे इम्प्रूव क्यों नहीं किया जाता ? इसके बारे में एक समस्या यह है कि इसका सर्विस कडर छोटा है। अगर यहां किसी का ट्रांसफर किया जाना है तो छोटी सी जगह है, उसी में ट्रांसफर हो सकता है। अगर यू० पी० में किसी का ट्रांसफर होता है तो बनारस से देहरादून किया जा सकता है तो सात सौ मील जगह है। यह किसी के लिये भी नियर पनिशमेंट हो सकता है। अगर दिल्ली का केडर हरियाणा, राजस्थान, यू० पी० के साथ हो तो यह स्थिति इम्प्रूव हो सकती है। छोटा केडर होने की वजह से इसमें एफीशियेंसी को इम्प्रूव करने की कम गुंजायश है। इस लिए कोई इफेक्टिव स्टेप्स भी नहीं लिया जा सकते।

कहा गया कि दिल्ली में पुलिस में सेंस आफ गिल्टीनेस है। अगर वे सेंस आफ गिल्टीनेस महसूस करते हैं तो इसका क्या इलाज। इसका शायद इलाज यही हो सकता है कि जिन्होंने गलतियां की हैं उन्हें सजा तो देनी ही है। इसका यह इलाज तो नहीं है कि भूल जाओ कोई सजा नहीं मिलेगी। यह इलाज तो हो सकता है कि उन्हें इंडीपेंडेंटली काम करने दिया जाए। पहले वे कदम-बकदम पर कोई काम करने से हिचकते थे। मैंने चार्ज लेने के बाद आई० जी० को बुलाया और कहा कि जिस तरह से राजनीतिक लोग डिमारेलाइज करते रहे हैं वह अब नहीं होगा। मैंने उनसे यह भी कहा कि आप किसी की सिफारिश न मानें। अगर जनता पार्टी के किसी लीडर की भी सिफारिश आये तो उसे भी न मानें। मैंने उन्हें साफ कह दिया कि आप मेरी सिफारिश भी न माने और ला के मुताबिक, कोशश के मुताबिक काम करें। अगर वे लोग रोज सिफारिशें मानने लगें तो साहब उनका इंडीपेंडेंटली काम करना मुश्किल होगा। हमने उन्हें यह भी कह दिया है कि पुलिस की तरफ से कोई गलत बात नहीं होनी चाहिय, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई गलत बात नहीं होगी।

यह कहा गया कि नो फायर आर्मस शुड बी यूज्ड। यह कैसे हो सकता है। जहां तक सीरियस क्राइम्स का ताल्लुक है, छोटे मोटे क्राइम्स की बात दूसरी है, उनमें तो पुलिस को करना ही पड़ेगा। अब हमने गुण्डों को बाहर भेज दिया, 15 दिन के बाद वे फिर आ गये। उनका क्या इलाज हो सकता है ? कुछ इलाज हम सोच रहे हैं। लकिन क्या यह मुमकिन हो सकता है कि आर्मस इस्तमाल न किये जायं। अगर क्रिमिनल्स को यह बात मालूम हो गयी तो क्राइम्स बढ़ेंगे, रूकेंगे नहीं। तो इस बारे में सजेशंस देने से पहले सोच लें कि इसका क्या नतीजा निकल सकता है।

SHRI K. LAKKAPPA: What about political violence?

चौधरी चरण सिंह : उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन पोलिटिकल है या नान पोलिटिकल है इसको आप तय करेंगे या सब इंस्पैक्टर तय करेगा ? इसकी डेफीनीशन बड़ी मुश्किल होती है।

Political violence and non-political violence has to be defined. What is "political" and what is "non-political is not easy to define. Ultimately, we will have to leave it to the discretion of the sub-inspector.

पंजाब की बात उन्होंने कही है। पंजाब में कांग्रेसी ओ के दफ्तर में आदमी को शूट

[चौधरी चरण सिंह]

किया गया है। लेकिन मैं तो उस बात का जवाब दे रहा था जो माननीय सदस्य ने इधर से उठाई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस फायर आम्र्ड यूज न करे। इसका जवाब मैं न दूं?

SHRI VAYALAR RAVI: The police are merely looking as onlookers helplessly when the house of the District Congress President has been burnt.

MR. SPEAKER: He has mentioned it and now repeated it.

SHRI K. LAKKAPPA: Politically large-scale violence is going on and that situation has not been controlled. Whether it relates to this party or that party is not material. Meetings are going on for the last few months.

चौधरी चरण सिंह : उन्होंने कहा कि जितनी वायलेंस अब की बार बिहार में हुई है पहले कभी नहीं हुई थी। अभी बहुत जल्दी में मैंने अपने अफसरों को नोट भेजा और पूछा कि बिहार में पिछले असेम्बली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में कोई वायलेंस हुई या नहीं हुई। माननीय सदस्य ने इम्प्रैशन दिया कि पहले कभी कुछ नहीं हुआ। मैं उनको सुनाना चाहता हूं कि पहले के आंकड़े क्या हैं। 1971 लोक सभा पोल के आंकड़े ले। पोल के पहले 29 इंसीडेंट हुए, इसके दौरान 122 हुए और सात उसके बाद हुए। 1972 के जो असेम्बली के इलैक्शन हुए उनमें 22 पोल के पहले 121 पोल के बीच और तीन उसके बाद —

एक माननीय सदस्य : मर्डर भी बता दें।

चौधरी चरण सिंह : दस हुए थे। 1977 लोक सभा पोल के ले लें। 122 पहले हुए, 89 बीच में हुए और कोई इंसीडेंट बाद में नहीं हुआ। शायद इस वास्ते नहीं हुआ कि मालूम हो गया था कि जनता पार्टी आ गई है। 10 मर्डर हुए और 16 इंजर हुए। अब की बार 45 इंसीडेंट पहले हुए, 74 बीच में हुए और बाद में एक हुआ। डैथ्स 25 हुई। एक साहब सौ कह रहे थे लेकिन 25 हुई। मैं कहूंगा कि एक भी नहीं होनी चाहिये। मेरे मित्र इम्प्रैशन दे रहे थे कि हैल बरपा हो गया है। वह कुछ अर्से तक वहां के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और मैं चाहता था कि वह जिम्मेदारी की बात कहते। ऐसी बात कहते जिस का असर पड़ता दस मरे, दस मरे और फिर दस मरे। अब की बार 25 मर गये। लेकिन एक ही इंसीडेंट में एक इंडिपेंडेंट और सी पी आई कैंडीडेट के झगड़े में दस एक ही बार में मर गये पच्चीस के अंदर। जो उन्होंने यह कहा कि ऐसी वायलेंस पहले कभी नहीं हुई इस वास्ते यह ठीक नहीं है।

बेलची विलेज की बात कही गई है। वहां से साढ़े 22 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस थाना है। पुलिस हर वक्त और हर जगह मौजूद रहे यह सम्भव नहीं हो सकता है। मकान के अन्दर घुस गये थे, बाद में पुलिस ने उनको कस्टडी में लिया, मकान जला डाला, इसको भी आप सुन लें। अब वहां पहुंचने के लिये कोई सड़क नहीं है। बहुत थोड़े फासले में सड़क है। यह भी मालूम हुआ है कि बिहार पुलिस के पास वहां जीप भी नहीं है। इस वास्ते सब इंस्पेक्टर पैदल चला बहुत दूर तक और देर में पहुंचा। लेकिन मान लो चार मील दूर यह इंसीडेंट होता जबकि यह साढ़े 22 किलोमीटर दूर है तब भी यह इंसीडेंट हो सकता था। थानों के पास चोरियां होती हैं डाके पड़ जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं। बड़े वैल एडमिनिस्टर्ड कंट्रीज में और टाउंज में इस प्रकार की घटनायें हो जाती हैं। बिल्कुल न हों यह मुमकीन नहीं है। मैं चाहता हूं कि होम मिनिस्ट्री पर खुल कर बहस हो जब बजट आये। जितने आप के यहां क्राइम्स हो रहे हैं वह नहीं होने चाहिये। लेकिन जिन कन्ट्रीज

को एडवान्स्ड कहा जाता है, सिविलाइज्ड तो मैं अपने ही देश को मानता हूं औरों के मुकाबले, तो एडवान्स्ड कन्ट्रीज में अगर आप अमरीका को ले लें वहां हर 10 साल में क्राइम डबल हो जाता है। उस के कुछ कारण हैं जिनकी डिटेल में जाना पड़ेगा। यहां दिल्ली में क्राइम हो गया, मर्डर हो गया, दो लड़कियों की रेपिंग हो गई और उन को मार दिया गया। एक अखबार में लिखा गया कि पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस क्या करती? 58 लाख दिल्ली की आबादी है। क्या पुलिस हर घर में रह सकती है? और दूसरी बात यह भी है कि दिल्ली की 36 लाख की आबादी पर जो पहले पुलिस फोर्स था वह फोर्स आज भी है। तो उन का रेक्रूटमेंट बढ़ना चाहिये। अब सवाल होता है कि दफ्तरों के लिये, रहने के लिये कंस्ट्रक्शन कहां से आये? जब रुपया इस काम के लिये पास करने की बात होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे सामने बैठे हुए ये लोग यही कहेंगे कि हम पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि यू०पी० में 90 परसेंट कांस्टेबिल्स के पास रहने को मकान नहीं हैं। फिर इन्वेस्टीगेशन के लिये जो एक्विपमेंट्स और फेसिलिटीज होनी चाहियें वह नहीं हैं। यह सब कहां से आये? तो अपने लिमिटेशन्स भी हमें समझने चाहियें।

बेलची गांव में जो घटना हुई उस को मेरे मित्र ने यह साबित करने की कोशिश की कि पुलिस अधिकारियों की गलती से यह कांड हो गया। मैंने अपने बयान में कहा था कि पांच मुकदमे उनके आपस में गैंगवार चल रहे हैं। मेरे मित्र ने कहा पुलिस वहां क्यों नहीं पहुंची। मकान ढाया, सेंध लगायी तब निकाला, मारा और उन को जलाया गया। थाने से दूर होने की वजह से पुलिस वहां पहुंच नहीं सकती थी। आपने पुलिस की कैलसनेस बतायी। मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस अफसरों को इन से क्या गेन होगा? फिर आप ने कहा कि इन्वेस्टीगेशन सी० बी० आई० को सुपुर्द कर दीजाये। तो सी० बी० आई० वाले भी तो पुलिस अधिकारी ही हैं। वहां के किस पुलिस अफसर की बाबत कह सकते हैं कि इस की वजह से हुआ। क्या पुलिस अफसर होना ही दोष है? ब्यूरोक्रेसी का शब्द कुछ बैड सेंस में इस्तेमाल होता है। लेकिन जितनी जिम्मेदारी सोसायटी का भला करने की सरकार लेती जायेगी उतनी ही ब्यूरोक्रेसी बढ़ेगी। आखिर ब्यूरोक्रेसी में भी तो हमारे और आप के ही भाई, भतीजे हैं। जो हमारा स्टैन्डर्ड है वही उनका होगा। इसलिये केवल अफसर हो जाने पर उन को कंडम करना ठीक नहीं है।

आपने कहा कि हम ने आर्डर दे दिया था कि अगर उन के जिले में रायट हुआ तो उन्हें डिसमिस कर दिया जायगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। बहुत दफा मैंने पढ़ा कि डी० एम० और एस० पी० को कह दूं कि अगर उन के जिले में रायट हुआ तो उनको डिसमिस कर दिया जायेगा। क्या इस से समस्या हल हो जायेगी। रायट हो सकता है बावजूद उनकी अच्छी इंटेंशन्स होने के मैं आपको बताऊं कि बस्ती जिले में 7,400 गांव है, कैसे रोक लेगा डी० एम० इतने बड़े जिले में रायट होने को? और अगर नहीं रोकता है तो वह डिसमिस हो जायेगा। तो क्या यह सम्भव है?

एक बात यह कही जाती है कि 30 अप्रैल से 15 जून के बीच में प्रेसीडेंट रूल लागू होने के बाद सिचुएशन वर्सन हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि प्रेसीडेंट रूल हो गया इसलिये वर्सन हो गई? नहीं हुई है। जैसे ही प्रेसीडेन्ट रूल हुआ अगले दिन ही जो हमने लेटर लिखा उसमें यही कहा है कि आपको ला एंड आर्डर मेनटेन करना है। दूसरी बात यह लिखी कि फ्री और फेयर इलेक्शन करना है इर्रेस्पेक्टिव आफ गेन्स और कंसीडरेशन। तीसरे हम ने देखा कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज करोड़ों करोड़ों रुपये खर्च कर के चली गई तो हमने उनको कहा कि जो खर्च आप रोक सकते हों उसको रोका जाये। यही तीनों डायरेक्शन्स हमने दिये

[चौधरी चरण सिंह]

थे । तो इलेक्शन्स में पैशन्स एरा एज हो जाते हैं बिना किसी कारण के उनको कोई रोक नहीं सकता है । मैं यू० पी० की एक मिसाल देता हूं । बदायूं जिला पंचायत के एक गांव में आठ आदमी मारे गये । अब लाठी उठी और ये मारे गये । अब यह कहना कि दिल्ली में बैठने वाले लोगों की यह नाकाबलियत है, तो नाकाबलियत तो है, लेकिन इसको क्या किया जाये ।

यह कहना कि 100 मर्डर्स इन बिहार, पंजाब में मर्डर हो गया तो ये कहां चले गये, कांग्रेस वाले मारे गये । तो कांग्रेस के दफ्तरों में ही एक आदमी मारा गया । कांग्रेस (आई) वालों के यहां एक आदमी उनके दफ्तर में ही फ्लैग या पोस्टकार्ड लेने गया था, वह कांग्रेस मैन ही था । गुंडे साथ थे, उसने वहीं उसे शूट कर दिया । बताइये इसमें जनता पार्टी की क्या जिम्मेदारी हो गई । कोई कहता है कि दिल्ली में गुण्डे गये । तो यह तो एडल्ट फ्रैंचाइज है, सब अपनी राय रखते हैं । अगर कोई वर्कर मर जाये तो कांग्रेस का भी हो सकता, जनता का भी हो सकता है । तो यह कहना ठीक नहीं होगा ।

काश्मीर में हमने कहा कि फ्री एंड फेयर इलैक्शन हों । हमारी पूरी कोशिश भी है लेकिन वहां बहुत ज्यादा पैशन्स हैं, प्रेजूडिस भी हैं । अधिकतर दो ग्रुप रहे हैं । वहां कुछ गड़बड़ हो गई । हमने मीसा में 121 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वहां और कोई ला था नहीं । हमने वहां के लोगों को कहा कि स्ट्रिक्टली मेन्टेन करें । जितना आपका गुस्सा है, जो आप चाहते हैं वही मेरी प्रतिक्रिया है । हमने यह भी कहा कि कोई मीटिंग डिस्टर्ब न हो, इसकी कोशिश करें । स्थिति कंट्रोल के बाहर नहीं है । अब कहते हैं कि पोलिटिकल वायोलेंस इन्क्रीज हो गई, यह बन्द नहीं हुआ । मैं फिगर्स क्वोट करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय 4 ही किस्म के जुल्म हैं । एक तो पोलिटिकल वायोलेंस है और एक एक्सट्रीमिस्ट वायोलेंस । जनता पार्टी के और कांग्रेस (आर) के लोग वायोलेंस में विश्वास नहीं करते, नैक्सलाइट कुछ करते हैं, सी० पी० आई० के लोग कुछ करते हैं जो कि हम लोगों से ज्यादा करते हैं, बतौर अपनी पालिसी के वह करते हैं, । लेकिन मैं बताता हूं कि एक्सट्रीमिस्ट वायोलेंस के 1975 के पूरे साल में 100 केसेज हुए थे और 1977 में जनवरी से जून तक कुल 17 केसेज हुए । 75-76 के फिगर्स हैं अप्रैल के 5 और मई में 1 । यह एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस हुई है ।

इलैक्शन की बात मैं बता चुका हूं कि जो पहले हुए हैं लेकिन अब की बार बिहार में ज्यादा हो गये हैं ।

स्टूडेंट्स वायोलेंस सन 1975 के मुकाबले में बढ़ी नहीं है । घटी भी नहीं है, लेकिन बढ़ी भी नहीं है । अप्रैल और मई महीने, जिसमें जनता पार्टी का चार्ज था इसको अगर कम्पेयर करेंगे तो टोटल इंसीडेंट्स 805 हुए थे और अप्रैल-मई 77 में 799 । इसमें कोई फर्क नहीं है । वायोलेंस इंसीडेंट्स पहले 181 हुए थे और अब की बार 125 हुए ।

लेबर के मामले में जो पहले स्ट्राइक्स हुए थे वह 150 थे अप्रैल से जून तक और अब की बार 600 के लगभग स्ट्राइक्स हुई, हैं । स्ट्राइक्स करने का राइट लेबर का है, उनके मन में रिजेंटमेंट था । स्ट्राइकस को हम इल-इलीगल नहीं मानते हैं । पहली बार 75 ला-लैसनैस के 64 मामले हुए थे और अब की बार 160,170 के करीब हो गये हैं । ये बेशक ज्यादा हैं, यह मैं तस्लीम करत

हूं लेकिन कारण बतलाता हूं कि दो महीने तक बहुत रिक्वैस्ट करके रक्खा गया था। उन्होंने कहा कि अंडरट्रायल्स भाग गये और जेल से प्रिजनर्ज भाग गये। भागते हैं—यही नहीं कि भागते हैं, भागते रहेंगे।

मैं माननीय सदस्यों का और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैंने खोसला कमीशन की रिपोर्ट मंगा रखी है। मुझे उसे पढ़ने का मौका नहीं मिला है। दिल्ली में पुलिस कमिश्नर रखने के बारे में एडमिनिस्ट्रेटर्ज में डिफरेंस आफ़ ओपीनियन बहुत ज्यादा है। सैंट्रल कमीशन के एपायंटमेंट के बारे में भी हमारे यहां विचार हो रहा है। माननीय सदस्य ने, जो दिल्ली की नुमायंदगी करते हैं, कहा है कि स्टेट लेवल पर कमीशन बैठे हैं, लेकिन सैंट्रल लेवल पर कोई कमीशन नहीं बैठा है। हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्दी हम उस का एनाउंसमेंट कर दें।

MR. SPEAKER: He House stands adjourned till 11 A. M. tomorrow.

19.31 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, June 16, 197e7/Jyaistha 26, 1899 (Saka).

GMGIPND—M—584 L S—8-7-77—998